employed Youth (SEEUY) provided they fulfil other eligibility criteria.

(b) Out of Rs. 89 crores allocated for 1991-92, so far Rs. 16.31 crores has been released to Andhra Pradesh, Goa, Haryana, Uttar Pradesh Rajasthan, Gujarat, Himachal Pradesh, Maharashtra Assam and some Institutions/Organisations for implementation of the programme.

लोगों में निरक्षरता

187. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में निरक्षर लोगों की संख्या बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि प्राथमिक शिक्षा पर किये जा रहे व्यय की राशि में शिक्षा प्रदान करने पर किए जा रहे कुल व्यय के अनुपात में कमी होती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो पंचवर्षीय योजनाओं में योजनावार इसकी प्रतिशता का ब्यौरा क्या था;

(घ) क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसकी प्रतिशतता बढ़ाने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर व्यय की प्रतिशतता क्या होगी ?

मानव संसाधन विकास (युवा कार्य और खेल विभाग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) यद्यपि 1981-1991 के दशक में निरक्षरों की वास्तविक संख्या में सीमान्तक वृद्धि हुई है, इस अवधि के दौरान 8.5 प्रतिशत की दशक वार्षिक वृद्धि दर, 1971-81 के दशक की (7.07 प्रतिशत) वृद्धि दर से अधिक थी।

(ख) और (ग) पिछली सात पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सम्पूर्ण शिक्षा पर व्यय में प्रारम्भिक शिक्षा पर योजनागत व्यय की प्रतिशतता का ब्यौरा निम्नलिखित है ।

योजनागत	सम्पूर्ण शिक्षा पर व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय
पहली . .	56.00
दूसरी . .	35.00
तीसरी . .	34.00
चौथी . .	30.00
पांचवी . .	32.10
छठी . .	30.50
सातवीं . .	33.00

(घ) और (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जा रही है।

Athreya Committee Report

188. SHRI DHULESHWAR MEENA:
SHRI RANJIT SINGH:
DR. JINENDRA KUMAR JAIN: :

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer the answer to Starred Question 63 given in the Rajya Sabha on the 17th July, 1991 and state:

(a) whether Government have since taken any final decision on the Athreya Committee Report on re-organisation of the telecom sector; and

(b) if so, what are the details thereof?